

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल जिला-नागौर

पीठारणीन अधिकारी :- श्री रवीन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)

जायल

ब्रह्मपुत्र

151/21

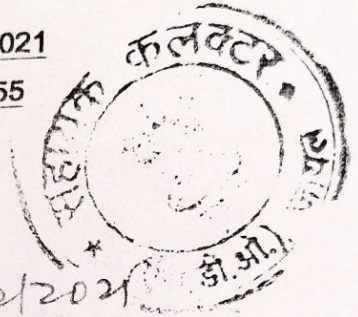
पारसकंवर पुत्री जतनकंवर

जाति-राजपूत निवासी आदर्श कॉलोनी डीडवाना रोड जायल जिला नागौर

25/12/21

1. श्यामसुन्दर पुत्र शिवकरण जाति जाट निवासी सियाको की ढाणी चुई तहसील डेगाना जिला नागौर
2. बबूलाल पुत्र रामनारायण जाति जाट निवासी जाटो की ढाणी माल्यावास जिला जयपुर
3. सरकार जरिये तहसीलदार जायल

प्रार्थना पत्र अधीन आदेश-7 नियम 11 सी.पी.सी. दिनांक 08.09.2021
वाद अधीन धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955



दिनांक : 30/12/2021

मुकदमा नं. 151/2021

- : : आदेश : :-

1. प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण (अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण) संख्या 1 श्यामसुन्दर ने एक प्रार्थना पत्र अधीन आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. दिनांक 08.09.2021 को हस्तगत प्रकरण में जरिये अधिवक्ता पेश किया। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को पत्रावली पर लिया गया तथा प्रतिलिपि वकील अप्रार्थी (वादी) को दिलाई गई। वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया की वादिनी ने न्यायालय हाजा में इकरारनामा के आधार पर खातेदारी घोषणा के लिए वाद अधीन धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया है जबकि वादीनी स्वयं द्वारा प्रार्थी श्यामसुन्दर के पक्ष में वैधान रजिस्ट्री करवाई जाकर कब्जा सुपुर्द किया इसी के आधार पर प्रार्थी को खातेदारी अधिकारी प्राप्त हुए है। उक्त प्रकरण में वादीनी स्वयं ने स्वीकार किया है कि 15000000 अक्षरे एक करोड़ पचास लाख रूपये प्रतिवादी से उधार लिये थे तथा उसी ऐवज में रजिस्ट्री करवाई थी तथा 1 वर्ष का कोल था। ऐसे इकरारामें के आधार पर माननीय न्यायालय हाजा को सुनवाई का अधिकार नहीं है क्योंकि उक्त इकरारनामों के अनुसार एक बहुत बड़ी राशि का विवाद है तथा माननीय न्यायालय हाजा को राशि से संबंधित विवाद तय करने का कोई हक अधिकार नहीं है; अतः वादीनी के वाद को सुनने का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार नहीं होने से एवं बर्ल बर्ड लों होने से खारिज किया जावे।

2. वकील अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अधीन आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. का जवाब पेश किया तथा प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 1 को स्वीकारते हुए अन्य पेराज को अस्वीकार करते हुये कथन किया कि वादिया ने खसरा नं. 2519 रकबा 5.9424 हैक्टेयर में से 1295/29712 है। जिस पर वादीनी का कब्जा काश्त व रहवासी फार्म बना हुआ है। ये तथ्य गलत है कि वादीनी पारस कंवर ने

PC

30/12/2021
कलक्टर
जायल

1

7 नियम 11 सीपीसी का अवलोकन किया जिसके तहत वाद पत्र निम्नलिखित दशाओं में नामजूर कर दिया जाएगा -

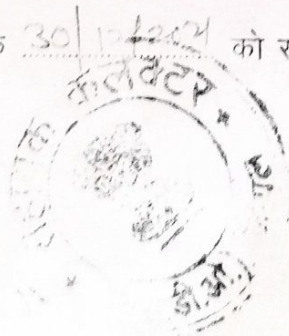
1. जहाँ वह वाद हेतुक प्रकट नहीं करता है।
2. जहाँ दावा कृत अनुतोष का मुल्यांकन कम किया गया है और वादी को मुल्यांकन को ठीक करने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किये जाने पर उस समयवधि के भीतर जो न्यायालय में नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता है।
3. जहाँ दावा कृत अनुतोष का मुल्यांकन ठीक है किन्तु वादपत्र अपर्याप्त स्टाम्पपत्र पर लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प पत्र के देने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किये जाने पर उस समयवधि के भीतर जो न्यायालय में नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता है।
4. जहाँ वाद पत्र में किये गये कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है।

प्रार्थना पत्र एवं वाद पत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पक्षकारान के मध्य एक बैचान रजिस्ट्री पंजिथन हुई है, साथ ही दो तीन इकरारनामे किये गये है जो की पंजिबद्ध नहीं है। वाद पत्र के पैरा संख्या 1 में उधार रकम कि ऐवज में रजिस्ट्री करवाया जाना अंकित है, वाद पत्र के पैरा संख्या 2 में इकरारनामे के आधार पर बैचान रजिस्ट्री के गिरवी का उल्लेख करते हुए उधार रकम चुकाने के कारण वादिनी उक्त भू-भाग पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने कि हकदार है। पैरा संख्या 3 में उक्त बैचान प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में किया जाना विहित है, पैरा संख्या 4 में वाद हेतुक गिरवी मकान कि रजिस्ट्री वादिनी के नाम करवाने से इनकार करने पर उत्पन्न हुआ अंकित किया है। प्रार्थना पत्र अधीन आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. में वाद पत्र एवं जवाब दावा का अवलोकन किया जाना होता है। हस्तगत प्रकरण में "जहा वाद पत्र में किये गये कथन से यह प्रतीत होता है वाद विधि द्वारा वर्जित है " पूर्णत लागू होता है क्योंकि वाद हेतुक बैचान रजिस्ट्री वापस वादिनी के नाम नहीं करवाये जाने पर पैदा हुआ जो कि अपजिंकृत इकरारनामे के आधार पर किया जाना था अर्थात इकरारनामे की पालना नहीं हुई है, इकरारनामे की पालना **specific performance, u/s 15 Specific Relief Act** के तहत सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार का प्रकरण है। अतः हस्तगत प्रकरण न्यायालय हाजा के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार नहीं होने एवं बार्ड बाई लॉ (विधि द्वारा वर्जित) होने से हम वकील प्रार्थीगण/प्रतिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अधीन आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. स्वीकार किये जाने योग्य समझते है।

- :: आदेश :: -

अतः प्रार्थना पत्र अधीन आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाता है तथा वादीनी का वाद अधीन धारा 88, 188 न्यायालय हाजा के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार नहीं होने एवं बार्ड बाई लॉ (विधि द्वारा वर्जित) होने से खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 30/12/2021 को सरे ईजलास लिखा जाकर सुनाया गया।



30/12/2021
 (रवीन्द्र कुमार) कलक्टर
 सहायक कलक्टर, जायल
 जिला-नागौर